‘संकट की घड़ी में राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के साथ है’

मुख्यमंत्री भजन लाल ने हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों को फोन पर राहत व बचाव में पूरे सहयोग का विश्वास दिलाया

■ मुख्यमंत्री भजन लाल ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सहायता हरियाणा व पंजाब के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचायें।

जयपुर, 1 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से दूरभाष पर वार्ता कर दोनों राज्यों में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए हरसंभव सहयोग देने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आपदा की इस घड़ी में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हरियाणा के प्रभावित जिलों और पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सतलज, व्यास और रावी नदियों में बढ़ते जल स्तर से उत्पन्न हालात पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति, जलभराव से हुए नुकसान और प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे चिकित्सा सुविधा सहित हर प्रकार की आवश्यक सहायता हरियाणा और पंजाब के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाएं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए कि वे राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराएं।

वाणिज्यिक एलपीजी के दाम घटे

नयी दिल्ली, 01 सितंबर। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार से वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है।

वहीं, 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम 51.50 रुपये तक घटाये गये हैं। अप्रैल से अब तक लगातार छठी बार इसमें कटौती की गयी है जबकि घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को अप्रैल के बाद राहत नहीं मिली है।

दिल्ली और चेन्नई में वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 51.50 रुपये सस्ता होकर क्रमशः 1,580 रुपये और 1,738 रुपये का हो गया है। कोलकाता में यह 50.50 रुपये और मुंबई में 51 रुपये सस्ता हुआ है। आज से कोलकाता में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 1,684 रुपये का और मुंबई में 1,531.50 रुपये का मिलेगा। इंडियन आयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन सस्ता होने की जानकारी भी दी गई।

बीकानेर में साढ़े पांच इंच वर्षा, कोटगेट पर वाहन बहे

शहर के कई मार्गों पर दो-तीन फीट पानी भरा, पी. बी. एम. अस्पताल के वॉर्ड तक पानी आया

■ पंचशती सर्किल एरिया में कारें दो-तीन फीट तक पानी में डूबीं। किसी गाड़ी की नंबर प्लेट गायब हो गई, किसी कार के अंदर पानी भर गया।

बीकानेर, (निसं)। यहां रविवार को हुई तेज बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया। क्षेत्र के गांवों में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, बीकानेर में साढ़े पांच इंच बारिश हुई। शहर में कई मार्गों पर दो-तीन फीट तक पानी एकत्र हो गया, तो कई जगह सड़क हादसे भी हुए। गनीमत है कि अब तक किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है।

जानकारी के अनुसार, बीकानेर में शाम को भी बारिश हुई और तो करीब आधा घंटे तक जारी रही। बारिश इतनी तेज थी कि कोटगेट पर खड़े वाहन बह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को कोटगेट के दरवाजे पकड़ कर खड़ा होना पड़ा। वहीं, ढोला मारु होटल से पंचशती सर्किल के बीच कारें तैरने लगीं। पब्लिक पार्क, कलेक्ट्री, केईएम रोड, रानी बाजार, रेलवे स्टेशन व डाक बंगले के पास भी भारी मात्रा में पानी एकत्र हो गया। पीबीएम अस्पताल के वार्ड तक में पानी आ गया।

जवाहर नगर में आशीर्वाद नर्सिंग होम के पास गजनेर की ओर से आ रही एक कार पलट गई। कई बार पलटते हुए यह कार बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे बिजली का खंभा बीच में से टूट गया। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली बंद थी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस कार में तीन युवक सवार थे, जिसमें एक को गंभीर चोट आई। इन लोगों ने जैसे-तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

करमीसर रोड पर भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई। प्रत्यक्षदर्शी योगेश व्यास ने बताया कि ये स्कोर्पियो तेज गति से आई और डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि इस हादसे में भी किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। बीकानेर के पंचशती सर्किल एरिया में एक कार दो से तीन फीट तक डूब गई। किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट गायब हो गई तो किसी की कार में पानी घुस गया। बीकानेर के जूनागढ़ के आगे बारिश आते ही तालाब बन जाता है। हर बार की तरह इस बार भी जेसीबी मशीन खड़ी करके रास्ता रोक दिया गया है। जिस कलेक्टरी पर पूरे शहर को आपदा से बचाने की जिम्मेदारी है, वहां भी पानी भरा रहा।

विधानसभा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

“राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक”को मार्च 2025 में बजट सत्र के दौरान इस पर व्यापक चर्चा के बाद प्रवर समिति के पास भेजा गया था। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ सदन में प्रस्तुत कर दी है। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया और सरकार मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कराने की दिशा में गंभीर है।

बाड़मेर से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी “खेजड़ी बचाओ” के पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सरकार से मांग की कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए एक ठोस और प्रभावी कानून लाया जाए।

सत्र की शुरुआत हमेशा की तरह श्रद्धांजलि सभा से हुई, जहां दिवंगत नेताओं और देशभर की विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों को याद किया गया। पूर्व राज्यपाल ला. गणेशन, सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा, आतंकी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया।

हालांकि इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान भी विवाद उत्पन्न हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि न दिए जाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे “मानवता के खिलाफ” बताते हुए कहा कि जब देशभर की घटनाओं को याद किया जा रहा है, तब राजस्थान की एक बड़ी त्रासदी को नजरअंदाज करना बेहद शर्मनाक है।

सत्र के दौरान युवा वर्ग से जुड़ा एक और अहम मुद्दा उठा - एसआई भर्ती विवाद। इस मामले पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़ म ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का विधिक परीक्षण कर रही है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को कतई नहीं बख्शेगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करेगी कि निर्दोष उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी न हो।

जोधपुर में तीन इंच वर्षा, रेलवे स्टेशन के बाहर व भीतर पानी भरा

मथुरादास माथुर अस्पताल व महात्मा गांधी अस्पताल के परिसरों में पानी भरा

■ जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जोधपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जोधपुर, 1 सितम्बर (कासं)। शहर में रविवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश सोमवार सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही, जिससे शहर का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार सुबह 8.30 बजे तक जोधपुर में तीन इंच बारिश हुई। शहर की प्रमुख सड़कों पर एक से दो फीट पानी भर गया। मथुरादास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में पानी भर गया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर भी पानी जमा हो गया। वहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर और भीतर भी पानी जमा हो गया।

बारिश के कारण जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जोधपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। कलेक्टर ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। बनाड़ रोड, रमजानजी का हत्था, सरदारपुरा, चौपासनी रोड, नेहरू पार्क, माता का थान चौराहा,चांदपोल से सूरसागर की ओर जाने वाले रास्तों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मथुरादास माथुर अस्पताल के सामने, रेलवे स्टेशन और शास्त्री नगर इलाके में भी पानी भरने की समस्या देखने को मिली। लगातार बारिश से शहर की कई सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम अलर्ट मोड पर हैं। रातभर हुई बारिश ने जोधपुर शहर को जलमग्न कर दिया। गनीमत रही कि बारिश रात में हुई, जब आवाजाही कम थी, वरना भारी नुकसान हो सकता था।

आरपीएससी सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया

अजमेर, 1 सितंबर (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने अपने पद से स्वैच्छिक इस्तीफ़ा दे दिया है और राज्यपाल को भेज दिया है। उनके इस्तीफ़े का सीधा संबंध हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।

अपने त्यागपत्र में डॉ. मंजू शर्मा ने लिखा है, “मैंने अपना पूरा कार्यकारी व निजी जीवन अत्यन्त पारदर्शिता व ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है, किंतु गत दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है, जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान अथवा किसी भी जाँच एजेंसी में न किसी प्रकार की कोई भी जाँच लंबित है और न ही मुझे किसी भी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है।” जानकारी के अनुसार, उनका कार्यकाल अभी अक्टूबर 2026 तक था।

‘उपराष्ट्रपति का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं और सांसदों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की गरिमा बनाए रखने” के नाम पर समर्थन देने की अपील की है। यह अपील खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में असरदार साबित हो रही है, जहाँ उन्हें दलीय सीमाओं के पार समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा की उम्मीदें तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, जिनके पास लोकसभा में 16 सांसद हैं। न्यायमूर्ति रेड्डी के तेलुगू भाषी होने के नाते, नायडू पर उनका अच्छा -खासा प्रभाव माना जा रहा है और उन्होंने नायडू से व्यक्तिगत आधार पर समर्थन मांगा है। हालांकि नायडू ने पिछले हफ्ते भाजपा नेताओं के साथ हुई मीटिंग के बाद सार्वजनिक रूप से भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की थी, लेकिन टीडीपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तथा सरकार द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजे जाने के निर्णय पर वे अप्रसन्न बताये जाते हैं। जिसे उन्होंने “अनावश्यक और गलत समय पर उठाया गया कदम” बताया।

द्रमुक पहले ही भाजपा उम्मीदवार का विरोध करने की घोषणा कर चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का रुख वैचारिक मतभेदों पर आधारित है, और उन्होंने “तमिल भावनाओं” से निर्णय के प्रभावित होने की अटकलों को खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अन्नाद्रमुक के कुछ राज्यसभा सांसदों ने भी न्यायमूर्ति रेड्डी को समर्थन का आश्वासन दिया है, जो दक्षिण भारतीय राजनीति में दुर्लभ गठजोड़ों की ओर संकेत करता है।

जहाँ बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने अभी तक अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अन्दरुनी सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति रेड्डी को उनसे सकारात्मक संकेत मिले हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मिलकर दक्षिण के सांसदों का अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि न्यायमूर्ति रेड्डी की गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक मूल्यों पर ज़ोर उन्हें राधाकृष्णन के मुकाबले बढ़त दिला सकता है, जो भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं। पिछले चुनावों की तुलना में, इस बार विपक्ष अधिक एकजुट नजर आ रहा है, जिससे क्रॉस-वोटिंग की संभावना कम मानी जा रही है, जो अक्सर विपक्षी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाती रही है। आप ने भी, अपने लगभग 12 सांसदों के साथ, अधिकारिक रूप से रेड्डी को समर्थन देने की घोषणा की है।

लेकिन भाजपा अब भी संसद में अपनी संख्यात्मक बढ़त पर भरोसा जता रही है। लेकिन अंदरूनी असंतोष और क्षेत्रीय दलों के विपक्ष की ओर झुकाव की संभावना ने उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव असामान्य रूप से अनिश्चित बना दिया है। जैसा कि एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा: “यह केवल उपराष्ट्रपति की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि भाजपा की अपने सहयोगियों और अपने ही सांसदों पर पकड़ की भी असली परीक्षा है।

‘जो जनता को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, “समाज में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, जो सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका लगाएँ। इससे नेताओं में अनुशासन आता है, क्योंकि सरकार में मंत्री भी वह काम नहीं कर सकते, जो अदालत का आदेश करवा सकता है।

लोकप्रिय राजनीति नेताओं और मंत्रियों के रास्ते में बाधा डालती है।” पिछले साल मंत्री ने उन अवसरवादी नेताओं पर चिंता जताई थी, जो हमेशा सत्ताधारी दल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है।

गडकरी ने यह भी कहा था कि कुछ नेता अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए मज़ाक में कहा था, मैं हमेशा मज़ाक में कहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करते हैं, उन्हें कभी सज़ा नहीं मिलती।

एसआई पेपरलीक में राईका सहित 23 को जमानत मिली

■ हाईकोर्ट ने 30 अन्य आरोपियों को पेपरलीक से जुड़े गंभीर अपराध होने के कारण जमानत नहीं दी।

जयपुर, 1 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरपीएससी के सदस्य रहे रामूराम राइका को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राइका के अलावा मामले से जुड़े 22 अन्य आरोपियों को भी अदालत ने जमानत दी है। लेकिन 30 अन्य आरोपियों पर पेपर लीक से जुड़े गंभीर अपराध होने के कारण जमानत नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने कुल 53 जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर ये आदेश दिए। फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 19 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रामूराम राइका के अलावा जिन्हें जमानत दी गई है इनमें श्रवणराम, जयराज सिंह, सुनील कुमार बेनीवाल, मनीषा सिहाग, श्याम प्रताप सिंह, संतोष, इंदुबाला, लोकेश शर्मा, राजेन्द्र कुमार यादव, विमला, शैतानाराम, छम्मी बाई, मोनिका, अरुण शर्मा, अरुण कुमार प्रजापत, इंद्रा, दीपक, बुद्धीसागर उपाध्याय व एक अन्य शामिल हैं।

दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ की चेतावनी

■ दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205 मीटर रिकॉर्ड किया गया

■ जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है।

नयी दिल्ली, 01 सितंबर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर तेजी से चढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकार ने नदी किनारे बाढ़ की चेतावनी जारी की है।

केन्द्रीय जल आयोग से अनुसार, आज रात आठ बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का स्तर 205.03 मीटर रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटे में इसके बढ़ कर 206.41 मीटर पर पहुंचने की आशंका है। यहां खतरे का स्तर 205.33 मीटर है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को आश्वस्त किया है कि दिल्ली सरकार और बाढ़ से जुड़े संबंधित विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बांधों के सभी गेट खुले हैं और कहीं भी पानी रुक नहीं रहा है। पानी का जितना तेज़ी से बहाव आ रहा है, उतनी ही तेज़ी से आगे भी निकल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 207 मीटर या उससे थोड़ा ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी। गुप्ता ने कहा कि यमुना के किनारे फ्लड प्लेन में पानी पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि वह नदी का प्राकृतिक हिस्सा है। इसके अलावा, बाहरी इलाकों में पानी के फैलने की आशंका नहीं है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है और सभी अधिकारी हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी है। पिछले छह महीने में जिस तरह से यमुना और नालों की डी-सिल्टिंग का काम किया गया है, उसका बड़ा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने यमुना तलहटी में बसे लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

‘वोट चोरी का खुलासा एटम बम है, अगला खुलासा हाइड्रोजन बम होगा’

■ राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के समापन पर जल्दी ही नया खुलासा करने की घोषणा की। उन्होंने यात्रा की सफलता के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया।

पटना, 01 सितंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि अभी तक हुआ वोट चोरी का खुलासा तो एटम बम था लेकिन अब आगे जिस खुलासे को उनकी पार्टी सामने लाने वाली है, वह हाइड्रोजन बम होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग और भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गांधी ने बिहार में सोमवार को समाप्त हुई वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वही अब बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के संविधान की हत्या करना चाहते हैं। गांधी ने बिहार के लोगो को उत्साह से वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने और देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए धन्यवाद दिया।

शिक्षक भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुए विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक करने में मुख्य भागीदार रहा है। वह राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का सदस्य था और उसे इस प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने का दायित्व सौंपा गया था। अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ अपराध करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उसके खिलाफ इस प्रकरण के अलावा, तीन अन्य प्रकरण भी दर्ज हैं। उसे जमानत नहीं दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बांसवाड़ा में 16 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को स्कूल गई थी। स्कूल से घर लौटने के लिए ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। तभी बाइक पर दो लड़के आए। एक लड़का उसके ही स्कूल का पूर्व छात्र था। उसने लड़की को बाइक पर घर छोड़ने की बात कही, लेकिन लड़की ने मना कर दिया।

इस पर दोनों लड़के उसे जबरन उठाकर ले गए। दोनों लड़कों ने शराब पीकर रेप किया और मारपीट की और उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी, जिससे वह बेहोश हो गई। 21अगस्त को उसे पीपलखूंट क्षेत्र में फेंककर भाग गए। पीड़िता को बांसवाडा से गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी सर्जरी की गई। एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन के अनुसार, बच्ची बुरी हालत में आई थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। आते ही उसका ऑपरेशन किया गया। अब उसे वार्ड में शिफ्ट किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में एक नाबालिग को डिटेन किया है।

अफगानिस्तान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के नूरग्राम ज़िले में चार लोगों के घायल होने की सूचना है। पंजशीर के अबशार ज़िले में पाँच घर नष्ट हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

मोदी, शी व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि उनकी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों की रक्षा करेगी। संसद के हालिया मानसून सत्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों सदनों को बताया कि सरकार टैरिफ के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

भारत और अमेरिका ने इस वर्ष मार्च 2025 में एक संतुलित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी, जिसका पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत ही नहीं, वरन् कैनडा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रणनीति कह सकते हैं। सीधे प्रतिबंध या औपचारिक बहिष्कार के बजाय, भारत उपभोक्ता भावना को नियंत्रित और प्रेरित कर रहा है।

पहला कदम है राष्ट्रवादी उपभोक्ता जागरूकता। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे अभियानों को अब देशी ब्रांडों की ओर खरीदारी को मोड़ने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। सूक्ष्म संदेश अमूल को कोका-कोला के मुकाबले, कैफे कॉफी डे को स्टारबक्स के मुकाबले, और रूपे को मास्टरकार्ड के मुकाबले खड़ा करते हैं-जहाँ गर्व और मूल्य दोनों का सहारा लिया जा रहा है। भले ही यह बदलाव आंशिक हो, यह प्रतिरोध का संकेत है।

दूसरा, भारत अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ नीतिगत उपायों का उपयोग कर रहा है। डिजिटल सेवा कर, डेटा स्थानीयकरण के कड़े नियम, और ओ एन डी सी जैसी घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने जैसे उपकरण, अमेरिकी कंपनियों का नाम लिए बिना, बाज़ार संतुलन को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये उपाय उपभोक्ता हितैषी और संप्रभुता समर्थक लगते हैं, न कि बदले की भावना से प्रेरित।

तीसरा, वित्तीय विकल्पों को बढ़ावा देना है। भारतीय रिज़र्व बैंक का लंबे समय से चल रहा प्रयास-रूपे और यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना-अब आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जब कोई भारतीय रूपे कार्ड का उपयोग करता है, तो वह एक चुपचाप विरोध का कार्य करता है।

चौथा, प्रतीकात्मक व्यापारिक जवाब चुने गए हैं। हर्ली-डेविडसन मोटरसाइकिलों, कैलिफ़ोर्नियाई बादामों या केंटकी बॉर्बन जैसे उत्पादों, जो अमेरिका की सांस्कृतिक पहचान है, पर बाजार में इनकी सीमित पहुंच है, पर शुल्क बढ़ाकर, भारत वॉशिंगटन को प्रतीकात्मक तौर पर झटका दे रहा है, बिना अपने उपभोक्ताओं को प्रभावित किए। अंततः, नैरेटिव का ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इन कदमों को प्रतिशोध की बजाय ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में प्रस्तुत करके, भारत ने ओछी राजनीति करने के आरोप से खुद को बचाया लेकिन जनता के गुस्से को रचनात्मक दिशा दी है। उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि वे बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि आत्मनिर्भरता की पुष्टि कर रहे हैं-एक सशक्तिकरण का संदेश, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं।

अमेरिकी आर्थिक दबाव और दोहरे मापदंडों के खिलाफ यह बहिष्कार लहर केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष का संकेत है। पेरिस से पंजाब तक, उपभोक्ता अमेरिकी वर्चस्व की कीमत पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भारत में ट्रंप के टैरिफ उल्टा असर कर सकते हैं: नई दिल्ली को घेरने की बजाय, उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को हवा दे दी है और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों को गति दी है।

यह कोई अल्पकालिक उबाल नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। अगर 146 करोड़ भारतीय, कैनडा और यूरोप के करोड़ों उपभोक्ताओं की तरह, अमेरिकी उत्पादों की खरीद में आंशिक रूप से भी कटौती करें, तो इसका संयुक्त प्रभाव गहरा हो सकता है। जो शुरुआत ट्रंप की टैरिफ चाल से हुई थी, वह शायद दशकों में अमेरिकी आर्थिक शक्ति के खिलाफ सबसे बड़ा उपभोक्ता-नेतृत्व वाला प्रतिरोध बन जाए।

शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप ने अपने अधिकृत प्रस्ताव में पहलगाम के आतंकवादी हमले को धिक्कारा

इसे भारत की कूटनीतिक सफलता माना जाता है, पर इसे पूर्ण सफलता भी नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रस्ताव में इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की भूमिका कोई जिक्र नहीं हुआ

■ यहां यह स्मरण करने योग्य है, कि गत 26 जून की एस.सी.ओ. की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री ने बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि बैठक के बाद अधिकृत रुप से जारी प्रस्ताव में पहलगाम के आतंकवादी हमले का कोई जिक्र भी नहीं किया गया था, जबकि, पाकिस्तान में हुई आतंकवादी हिंसक घटनाओं का विवरण दिया गया था।

तियानजिन, 01 सितंबर। चीन में हुई एससीओ की बैठक में एक तरफ पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है, तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। बैठक खत्म होने के बाद शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों ने जो घोषणापत्र जारी किया है, उसमें भारत के जम्मू-कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया।

एससीओ की बैठक के बाद आज सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणापत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि सभी सदस्य देशों की मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना हैं। यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो बात भारत लंबे समय से कहता आया है, वह भी एससीओ के घोषणापत्र में है। भारत कहता आया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एससीओ के घोषणापत्र में भी यह लाइन दर्ज की गई है कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों सहित, आतंकवाद का मुकाबला करने का आव्हान करते हैं। एससीओ के घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। ज्ञातव्य है कि इस साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान, एससीओ के घोषणापत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जताई थी। साथ ही इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

भारत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप पर दुख जताया और कहा भारत से हर सभंव सहायता दी जाएगी।

डा.जयशंकर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी से बात की। भूकंप में हुई जान-माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत ने आज काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुँचाए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908